



2026:

AHC:57630

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2027 सन् 2026

निर्दोष कुमार

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता

: अवनीशा कुमार, नरेंद्र सिंह

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री नरेंद्र सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री बी.पी. मौर्य को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन मामला अपराध संख्या 65 सन् 2025, भा0द0सं0 की धारायें 420, 467, 468, 406, 342, 120-बी के अन्तर्गत, थाना मिलक, जिला रामपुर में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी सुनील कुमार सचान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 03.12.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-18591 सन् 2025 में पारित आदेश द्वारा नियमित जमानत दी जा चुकी है और एक अन्य सह-आरोपी रिया सचान को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या-208 सन् 2026 में पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक की भूमिका सह-आरोपी व्यक्ति से भिन्न नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।
5. आवेदक और सह-आरोपियों ने कथित तौर पर प्रथम सूचनाकर्ता से सरकारी नौकरी दिलाने के झूठे वादे पर धन प्राप्त किया था। सुनील कुमार सचान और रिया सचान को पहले ही जमानत मिल चुकी है और आवेदक की भूमिका सह-आरोपियों से अलग नहीं है।
6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की यथार्थ भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।
7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।
8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदक- निर्दोष कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-
 - (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे/उसकी/ उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
 - (iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति, जितेंद्र

कुमार सिन्हा)

18 मार्च, 2026

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"